

आयकर आयुक्त, सेलम

बनाम

पी. वी. कल्याणसुंदरम

सितंबर 14, 2007

[एस. बी. सिन्हा और हरजीत सिंह बेदी, जे. जे.]

आय कर अधिनियम, 1961 - धारा 260 क - 4.10 लाख रुपये में भूमि खरीदने वाला निर्धारिती - निर्धारिती से छापे के दौरान खुली शीटों पर नोट बरामद किए गए। विक्रेता के बयान के आधार पर विभाग, हालांकि इसके विपरीत कि बिक्री अधिक मूल्य के लिए थी और उसके आधार पर मूल्यांकन करना - सी. आई. टी. और न्यायाधिकरण ने निर्धारिती के पक्ष में निर्धारित किया - धारा 260 के तहत अपील। संपत्ति के वास्तविक बिक्री मूल्य, विक्रेता द्वारा दिए गए बयानों और जवाबी बयानों के प्रभाव, खुली शीटों पर बरामद किए गए नोटों पर निर्भरता के संबंध में कानून के महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए: - उच्च न्यायालय द्वारा खारिज - हस्तक्षेप किया गया - अभिनिर्धारित किया गया: उच्च न्यायालय के आदेश में कोई खामी नहीं है - इस प्रकार उठाए गए प्रश्न सभी तथ्य के प्रश्न थे न कि कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न।

निर्णय/आदेश-किसी प्राधिकारी के आदेश से उद्धरण का लेखन, विशेष रूप से एक विशेष आदेश को उद्धृत करना -का औचित्य - अभिनिर्धारित किया गया: स्वयं को गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह प्रक्रिया अक्सर संक्षिप्तता और सटीकता बनाने में मदद कर सकती है, लेकिन किसी भी 'लिए गए शब्द' का उपयोग किया जाता है किसी निर्णय को वास्तविक लेखक के प्रति शिष्टाचार के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

प्रत्यर्थी-निर्धारिती ने कुछ भूमि खरीदी थी। बिक्री विलेख बिक्री मूल्य 4.10 लाख रुपये दिखाए गए। कुछ परिसरों की तलाशी के दौरान, विभाग को कथित रूप से प्रतिवादी के हाथों में खुली शीटों पर कुछ नोट मिले और प्रतिवादी इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका। विभाग ने विक्रेता का बयान दर्ज किया कि उसे बिक्री के रूप में 34.85 लाख रुपये प्राप्त हुए थे। इसके बाद विक्रेता ने विरोधाभासी बयान दिया और फिर पहले वाले बयान पर लौट आया। निर्धारण अधिकारी ने मूल्यांकन के लिए बिक्री प्रतिफल के रूप में 34.85 लाख रुपये लिए और अघोषित आय के रूप में 3,75,005 रुपये जोड़े। आयकर आयुक्त और न्यायाधिकरण दोनों ने निर्धारिती के पक्ष में फैसला सुनाया। अपीलकर्ता-राजस्व ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 260क के तहत अपील दायर की, जिसमें कानून के महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए कि क्या राजस्व घोषित की तुलना में अधिक बिक्री विचार राशि तय करना उचित था; जब निर्धारिती ने पाई गई टिप्पणियों पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और राजस्व वास्तविक बिक्री मूल्य के निर्धारण के लिए विक्रेता के बयान के साथ इसकी पुष्टि करने में सक्षम था, तो क्या निचले प्राधिकारी का हस्तक्षेप उचित था; और जब तलाशी के समय पाए गए सबूतों के साथ लगातार शपथ ली गई बातों पर विचार किया गया, तो क्या पहले के विरोधाभासी बयानों के बीच एक बयान के आधार पर सभी को खारिज कर दिया जाएगा। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर अपील को खारिज कर दिया कि विचार के लिए कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया:

यह सच है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने न्यायाधिकरण और आयुक्त के आदेशों से व्यापक रूप से उद्धृत किया था जैसे कि वे स्वयं लेखक थे। किसी प्राधिकारी, विशेषकर किसी विशेष प्राधिकारी के आदेश को उद्धृत करने में गलती नहीं की जा

सकती क्योंकि यह प्रक्रिया अक्सर संक्षिप्तता और परिशुद्धता बनाने में मदद कर सकती है, लेकिन किसी फैसले में इस्तेमाल किए गए किसी भी 'लिए गए शब्द' को सच्चे लेखक के प्रति शिष्टाचार के रूप में किसी भी उचित तरीके से स्वीकार किया जाना चाहिए। फिर भी, उठाए गए सवाल किसी भी तरह से कानून के ठोस सवाल नहीं कहे जा सकते। संपत्ति के वास्तविक बिक्री मूल्य के तथ्य, विक्रेता द्वारा दिए गए विरोधाभासी बयानों के निहितार्थ या क्या छापे के दौरान बरामद की गई खुली शीटों पर भरोसा किया जा सकता है, ये सभी तथ्य के प्रश्न हैं इसलिए, इसमें कोई दुर्बलता नहीं है उच्च न्यायालय का आदेश (पैरा 6) (953-ख, ग, घ, ङ)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4262/2007

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा कर प्रकरण (अपील) संख्या- 138/2006 में दिनांक 08.02.2006 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न।

अपीलार्थी की ओर से: जी. ई. वाहनवती, सॉलिसिटर जनरल, हृषिकेश बरुआ और बी. वी. बलराम।

प्रतिवादी की ओर से: के. स्वामी, यूसा लाचेनपा और प्रभा स्वामी।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश हरजीत सिंह बेदी द्वारा दिया गया था

1. अनुमति दी गई।

2. विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ के दिनांक 08 फरवरी 2006 के फैसले के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत राजस्व द्वारा आयकर अधिनियम 1961 (इसके बाद इसे "अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 260क के तहत दायर की गई अपील है। आयकर न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ

कथित तौर पर कानून के सवाल उठाने को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि वास्तव में कानून का कोई महत्वपूर्ण सवाल विचार के लिए नहीं उठा है। अपील के तथ्य इस प्रकार हैं:-

3. प्रतिवादी-निर्धारिती ने दिनांक 26.10.1998 के एक पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से बृंदावन रोड, फेयरलैंड्स, सेलम में 4.10 लाख रुपये की राशि में कुछ भूमि खरीदी। पॉलिमर नेटवर्क के कार्यालय और आवासीय परिसर की तलाशी के दौरान, प्रतिवादी के हाथ में कथित तौर पर खुली शीटों पर कुछ नोट पाए गए और विभाग द्वारा जब्त कर लिए गए। 8.12.1998 को दर्ज किए गए अपने बयान में, निर्धारिती ने कहा कि उसे याद नहीं है कि टिप्पणियाँ क्यों की गई थी। 11.12.1998 को एक अन्य बयान द्वारा इस कथन की पुष्टि की गई। विभाग ने 8.1.1998 को विक्रेता राजरथिनम का बयान भी दर्ज किया, जिसकी पुष्टि 11.12.1998 को की गई, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें वास्तव में कुल रुपये 34.35 लाख और वह बिक्री विलेख में दर्शाए गए 4.10 लाख रुपये की राशि उसे डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से और शेष नकद में प्राप्त हुए थे। हालाँकि राजरथिनम 8.1.1999 को अपने बयान से मुकर गए और एक हलफनामा दायर किया कि बिक्री मूल्य केवल 4.10 लाख रुपये थे और अधिकारियों को पहले दिए गए उनके बयान गलत थे। 20.11.2000 को दर्ज किए गए एक बाद के बयान में राजरथिनम फिर से अपने पिछले हिस्से में वापस आ गया और कहा कि बिक्री मूल्य रुपये 4.85 लाख थे निर्धारण अधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि बिक्री प्रतिफल वास्तव में 34.85 लाख रुपये थे न कि 4.10 लाख रुपये जैसा कि विक्रय पत्र में लिखा गया था। उन्होंने तदनुसार निर्धारण के प्रयोजन के लिए उपरोक्त बढ़े हुए आंकड़े रुपये 3.75.005 को माना और इसे 1.4.1998 से 8.12.1998 तक की अवधि के लिए अघोषित आय के रूप में माना। इसके बाद मामला आयकर आयुक्त (अपील) के पास ले जाया गया, जिन्होंने पूरे मामले की जांच करने के बाद पाया कि राजरथिनम द्वारा दिए

गए बयानों पर अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसी संपत्ति के लिए अधिकारियों द्वारा तय की गई न्यूनतम कीमत बहुत अधिक थी। यदि विक्रय विलेख 34.85 लाख रुपये पर पंजीकृत किया गया होता, तो उस मूल्य से कम होता। तदनुसार आयुक्त ने जोड़ी गई राशि हटा दी। इसके बाद राजस्व द्वारा आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष आयुक्त के आदेश के खिलाफ अपील की गई। न्यायाधिकरण ने 6 जुलाई 2005 के अपने आदेश में कहा कि कागज के खुले टुकड़ों पर टिप्पणियाँ जिनके आधार पर कम मूल्यांकन के संबंध में प्रारंभिक संदेह उठाया गया था, अस्पष्ट थे और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था क्योंकि ऐसा प्रतीत होता था कि कुल विक्रय विलेख के संबंध में क्षेत्र और खुली शीटों में परिलक्षित विसंगति थी। यह भी देखा गया कि पंजीकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित तिथि पर पंजीकरण के लिए उचित मूल्य 244/- रुपये से 400/- रुपये प्रति वर्ग फीट था और राजस्व द्वारा दावा किया गया 850/- रुपये प्रति वर्ग फीट की बिक्री पर विचार किया गया था। अवास्तविक और जमीनी स्थिति की अनदेखी की गई। आगे यह माना गया कि अतिरिक्त के आधार पर निर्धारित लगभग 1,84,000/- रुपये का कर यह नहीं दिखाएगा कि निर्धारिती ने विभाग द्वारा की गई अतिरिक्त राशि को स्वीकार कर लिया है या यह जमा राशि के रूप में बिक्री मूल्य का निर्णायक सबूत था। अधिनियम की धारा 158 ख, घ के तहत कार्यवाही शुरू होने पर, खुद को राजस्व से और अधिक उत्पीड़न से बचाने और अघोषित आय पर कर के भुगतान के लिए बहुत अधिक दायित्व से बचने के लिए एक स्पष्ट प्रयास में किया गया है। इन निष्कर्षों पर, न्यायाधिकरण ने अपील खारिज कर दी। इन्हीं परिस्थितियों में धारा 260 क के तहत उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई थी। उच्च न्यायालय के समक्ष कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए:-

(क) जब विक्रेता के रिटर्न और विवरण वास्तव में प्राप्त उच्च बिक्री प्रतिफल को स्वीकार करते हैं, तो घोषित की गई राशि से अधिक राशि पर बिक्री प्रतिफल तय करना उचित है या नहीं?

(ख) जब निर्धारिती द्वारा पाई गई टिप्पणियों पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और साथ ही राजस्व वास्तविक बिक्री मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से विक्रेता के बयान के साथ इसकी पुष्टि करने में सक्षम है, तो क्या निचले प्राधिकारी को उसी में हस्तक्षेप करने में उचित ठहराया जाएगा?

(ग) जब तलाशी के दौरान पाए गए साक्ष्यों के साथ लगातार शपथ ली गई बातों पर विचार किया गया, तो सभी को पहले के खंडन के बीच एक बयान के आधार पर खारिज कर दिया जाएगा, जिसे धमकी के परिणामस्वरूप भी समझाया गया था।

4. उच्च न्यायालय ने आयुक्त और न्यायाधिकरण के आदेश पर बहुत अधिक भरोसा करते हुए अभिनिर्धारित किया कि कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं उठाया गया था और तदनुसार अपील को खारिज कर दिया गया। यही स्थिति है कि वर्तमान प्रकरण हमारे सामने है।

5. श्री जी.एन.वाहनवती, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने शुरू में ही उच्च न्यायालय के आदेश पर गंभीर आपत्ति जताई है, जिसमें कहा गया है कि खंडपीठ ने अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए केवल आयुक्त और न्यायाधिकरण के आदेश के पर्याप्त हिस्से की नकल की है और इस पर कोई स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं किया है। कानून के जो प्रश्न विचारार्थ उठे थे, उन पर विचार किया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि बयानों के निहितार्थ और राजरथिनम द्वारा दिए गए जवाबी बयानों से संबंधित कानून के कई प्रश्न मामले में उठे थे और मामले को उस परिप्रेक्ष्य में उच्च न्यायालय द्वारा नहीं

निपटाया गया था और इसलिए यह उचित था कि मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए भेजा जाए। निर्धारिती प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने हालांकि बताया है कि विशेष रूप से आयकर आयुक्त ने मामले की बहुत विस्तृत चर्चा के बाद, लेनदेन की प्रकृति के संबंध में तथ्य की खोज पर निष्कर्ष निकाला था और यह दृष्टिकोण ठीक इसी प्रकार न्यायाधिकरण द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने तदनुसार प्रस्तुत किया है कि इस मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं उठाया गया है और उठाए गए मुद्दे पूरी तरह से तथ्य के प्रश्न थे।

6. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख का अध्ययन किया है। यह सच है कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने न्यायाधिकरण और आयुक्त के आदेशों से बड़े पैमाने पर उद्धृत किया है और उन्हें ऐसे पारित कर दिया है जैसे कि वे स्वयं लेखक हों। हमारा मानना है कि किसी प्राधिकारी, विशेषकर किसी विशेष प्राधिकारी के आदेश को उद्धृत करने में गलती नहीं की जा सकती क्योंकि यह प्रक्रिया अक्सर संक्षिप्तता और परिशुद्धता बनाने में मदद कर सकती है, लेकिन हम श्री वाहनवती से इस हद तक सहमत हैं कि किसी भी 'उद्धृत शब्द' का उपयोग किया जाता है। किसी निर्णय को वास्तविक लेखक(लेखकों) के प्रति शिष्टाचार के रूप में किसी भी उचित तरीके से स्वीकार किया जाना चाहिए। जो भी हो, हमारी राय है कि ऊपर दिए गए तीन प्रश्न, किसी भी तरह से, कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं कहे जा सकते। संपत्ति की वास्तविक बिक्री कीमत के बारे में तथ्य, राजरथिनम द्वारा दिए गए विरोधाभासी बयानों का निहितार्थ या क्या छापे के दौरान बरामद की गई खुली शीटों पर भरोसा किया जा सकता है, ये सभी तथ्य के प्रश्न हैं। इसलिए हमें उच्च न्यायालय के आदेश में कोई खामी नहीं दिखती। तदनुसार, हम अपील खारिज करते हैं।

एन.जे.

अपील खारिज की गई।

(यह अनुवाद एआई टूल: सुवास की सहायता से अनुवादक विनोद कुमार द्वारा किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।